



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 22 जून, 2010 / 1 आषाढ़, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 जून, 2010

संख्या: सिंचाई 11-40/2008-कुल्लू—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव देऊधार फाटी खराहल तहसील व जिला कुल्लू में जल भण्डार टैंक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी/कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र बिघा/बिस्वा में
कुल्लू	कुल्लू	देऊधार फाटी खराहल	7327/1	0-03

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 जून, 2010

संख्या सिंचाई 11-16/2010-मण्डी.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रव्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कनैड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप व जल भण्डार तरोट के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	विघा/विस्वा/विस्वांसी
मण्डी	सुन्दरनगर	कनैड़/6	324/1	0-06-05

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171002, 19 जून, 2010

संख्या सिंचाई 11-20/2010-मण्डी.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल भरजवाणू तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में नलकूप भरजवाणू (तलवाली) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	विघा/विस्वा/विस्वांसी
मण्डी	सुन्दरनगर	भरजवाणू/9	205/1	0-05-00

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171002, 18 जून, 2010

संख्या सिंचाई 11-8/2009-बिलासपुर.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव री रन्डोह तहसील झण्डूता जिला बिलासपुर में उठाऊ सिंचाई योजना री रडोह के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र विघा-विस्वा में
बिलासपुर	झण्डूता	री-रन्डोह	9/1	0-05

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 जून, 2010

संख्या सिंचाई 11-25/2010-सोलन.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महोल तहसील अर्की जिला सोलन में L.W.S.S टकरोग दोहची (महोल) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र विघा-विस्वा में
सोलन	अर्की	महोल	30	06-01

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171002, 19 जून, 2010

संख्या सिंचाई 11-24/2010-चम्बा.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव संधैहण तहसील डलहौजी जिला चम्बा में कूहल सिंचाई योजना कैहलु रैणा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
चम्बा	डलहौजी	संधैहण	453 / 1	0-00-07
			454 / 1	0-00-03
			457 / 1	0-00-16
			458 / 1	0-01-06
			किता-4	0-01-32

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171002, 18 जून, 2010

संख्या सिंचाई 11-17/2010-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल वहादपुर तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवं एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र	क्षेत्र	में
कांगड़ा	फतेहपुर	वहादपुर			हेक्टर	
			737/1	0	00	70
			737/3	0	00	45
			738	0	01	51
			739/2	0	12	56
			1516/1	0	00	18
			1517/1	0	02	18
			1523/1	0	04	53
			1523/2	0	02	76
			1626/1	0	04	95
			1626/2	0	01	10
			1631/1	0	01	94
			1634/1	0	03	34
			1636/1	0	07	24
			1643/1	0	02	28
			1644/1	0	00	04

1645	0	00	18
1646/1	0	02	90
1647	0	01	25
1648/1	0	01	14
1648/3	0	00	62
1791/1	0	00	63
1790/1	0	17	68
1836/1	0	01	02
1837/1	0	01	54
1876/1	0	00	29
1876/3	0	00	48
1878	0	01	36
1879/1	0	02	02
1879/3	0	09	91
1880/1	0	00	98
1885/1	0	01	67
1886/1	0	01	76
1901/1	0	00	96
Kittas-33	0	92	15

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / —
प्रधान सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

ख अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 मई, 2010

संख्या जी0ए0डी0-बी(ए)3-6/2008.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सचिवालय में सफाईकर्ता, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सचिवालय सफाईकर्ता, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी0ए0बी0 1ए (3)17/97 तारीख 27-09-1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सचिवालय, सफाई कर्मचारी (स्वीपर) वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 1999 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव ।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में सफाईकर्ता, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—सफाईकर्ता
2. पदों की संख्या.—4 (चार)
3. वर्गीकरण.—वर्ग-IV (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : वेतनमान 4900—10680 रूपए के पे बैंड +(जमा) 1300 —रूपए ग्रेड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धिया: 6200/— रुपये (स्तम्भ संख्या 15 के में दिये गए ब्यौरे के अनुसार) प्रति मास ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृंद को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त

किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती अभिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—
अनिवार्य : (क) हिन्दी या अंग्रेजी में पढ़ने या लिखने की जानकारी होनी चाहिए ।

वांछनीय अर्हता : (ख) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—लागू नहीं ।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद/पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि भर्ती प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15 क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी ।

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय के कार्यालय में सफाईकर्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.—सचिव, राज्यपाल, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और इन नियमों में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(ग) चयन, नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त सफाईकर्ता को 6200/—रुपये (पद के वेतनमान में न्यूनतम पे बैंड + ग्रेड पे के बराबर) समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ती की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में संविदात्मक रकम के 3 प्रतिशत के बराबर राशि वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—सचिव, राज्यपाल नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/—रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गये वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम के 3 प्रतिशत के बराबर राशि की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा तथा अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठता/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य/डियूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक ही स्थान पर पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर

अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमिति कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बावत जारी किये आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

सफाईकर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्रीनिवासी
.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....किया गया है।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सफाईकर्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार सफाईकर्ता के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....
....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/—रूपये प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सफाइकर्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त सफाइकर्ता को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनूमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सफाइकर्ता कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी एक ही स्थान पर पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था में प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पनुः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department's Notification No. GAD-B-(A) 3-6/2008 Dated-11-5-2010 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section**

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th May, 2010

No. GAD-B-(A)3-6/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Sweeper—Class-IV (Non –Gazetted) in Himachal Pradesh Governor's Secretariat as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Sweeper, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Saving.—(1) The Himachal Pradesh Governor's Secretariat Sweeper, Class-IV (Non-Gazetted) (Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules notified vide this Department's Notification- No.: GAB-1A(3)-17/97 Dated 27-09-1999 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been made valid under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary.

Annexure-“A”

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SWEEPER CLASSIV,
(NON-GAZETTED) IN THE GOVERNOR'S SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH**

- 1. Name of the post.**—Sweeper
- 2. Number of posts.**—Four(4)
- 3. Classification.**—Class-IV (Non-Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**— (i) **Pay Scale for Regular Incumbents:** Pay Band in the Scale of Rs 4900-10680 + Grade Pay Rs. 1300/-.
- (ii) **Emoluments for Contract employees :** Rs 6200/- contractual fixed amount (as per details given in Col. 15-A.) per month.

5. Whether Selection post or non-selection post.—N.A.**6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.**

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his adhoc or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relax- able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax-able at the discretion of the recruiting agency in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.—**ESSENTIAL :** (a) Should know to read or write in Hindi or English. **DESIRABLE QUALIFICATION:** (b) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Himachal Pradesh.

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Not Applicable.

9. Period of probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, Transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—N.A.

12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority.

15-A Selection for appointment for the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under the policy the **Sweeper** in the Governor's Secretariat, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB.—**The Secretary to Governor after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading News papers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Sweeper** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month(which shall be equal to minimum of the Pay band in the Scale + Grade Pay) . An amount equal to 3% of the Contractual amount as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary to Governor H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *vivavoce* test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e Secretary to Governor.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. Secretary to Governor from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-B** appended to these Rules.

TERMS & CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month.(Which is equal to the minimum of the Pay band of the Scale + Grade pay) . The contract appointee will be entitled for increase in Contractual amount @ 3% of the minimum of Pay Band +Grade pay of the post for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales etc. shall be given.

- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The Woman candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/Scheduled Tribes /other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons or posts.

Form of contract/agreement to be executed between the Sweeper and the Government of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh

This agreement is made on this -----day of -----in the year between Shri/Smt.-----S/OD/O Shri -----R/O-----
-----contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND the Governor of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Sweeper** on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Sweeper** for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____. And information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **6200/-** per month.
3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual **Sweeper** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Sweeper**. He will not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Sweeper** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of Women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1 -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2010

संख्या जी.ए.डी-बी.-(ए)3-2/2008.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या जी.ए.डी. 1ए (3)-3/97 तारीख: 18-11-1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम 1999 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई भी नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव ।

“उपाबन्ध—क”

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में चालक वर्ग—III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—चालक ।
2. पदों की संख्या.—3(तीन) ।
3. वर्गीकरण.—वर्ग—III (अराजपत्रित) ।
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान: वेतन बैंड रू0 5910-20200 ग्रेड वेतन रू0 2000
- (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां.—रू0 7910/— की संविदात्मक रकम प्रतिमास कॉलम 15—क में दिए गए ब्यौरे अनुसार, संदत की जाएगी ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद(पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती अभिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं—(क) अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से आठवीं या इसके समतुल्य परीक्षा पास हो ।

(ii) पहाड़ी क्षेत्र में हल्के/भारी वाहन चलाने की विधिमान्य ड्राईविंग लाइसेंस (चालन अनुक्षति) रखता हो ।

(ख) वांछित अर्हतायें : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—लागू नहीं ।

9. परीक्षा की अवधि यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर, ऐसा न होने पर सेक्रेण्डमेन्ट/स्थानान्तरण के आधार पर । संविदा के आधार पर, नियुक्त कर्मचारी कॉलम 15—क में दर्शाई गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सेक्रेण्डमेन्ट/स्थानान्तरण द्वारा ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन अभ्यर्थी की मौखिक परीक्षा तथा गाड़ी चलाने तथा गाड़ी का रख-रखाव की व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा ।

व्यवहारिक परीक्षा हेतु विभागीय भर्ती समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों के अतिरिक्त मोटरयान निरीक्षक, सहायक अभियन्ता यांत्रिक, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और प्रबन्धक/फौरमैन हिमाचल पथ परिवहन निगम से होगा । व्यवहारिक परीक्षा पास करना आज्ञापक होगा ।

15 क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय, में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.—सचिव, राज्यपाल, पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों का ब्यौरा कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताएं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त चालक को 7910/—रुपए (वेतन बैंड के न्यूनतम + ग्रेड वेतन के बराबर) की समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्तवर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में संविदात्मक रकम के 3 प्रतिशत के बराबर राशि वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7910/—रुपये की नियत संविदात्मक रकम (वेतन बैंड के न्यूनतम + ग्रेड वेतन के बराबर) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में पद के वेतन बैंड के न्यूनतम + ग्रेड वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सम्बद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए भी संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति तैनाती के एक ही स्थान पर पाचं वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.—उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बावत जारी किये अनुदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध—“ख”

चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्रीनिवासीसंविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ----- को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में से प्रारम्भ होने औरको समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7910/—रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक चालक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त चालक को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदात्मक चालक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात्, आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ जी0 पी0एफ0/ई0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department's Notification No. GAD-B-(A)3-2/2008 Dated 24-5-2010 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, 24th May, 2010

No. GAD-B-(A)3-2/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver, Class-III (Non-Gazetted) in Himachal Pradesh Governor's Secretariat as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Driver, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Governor's Secretariat Driver, Class-III (Non-Gazetted) nonministerial services Recruitment and Promotion Rules 1999 notified vide this Department's Notification No.:GAB- I A (3) -3 /97 Dated 18-11-1999 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been made validly under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRIVER (CLASS-III, NON-GAZETTED) IN THE GOVERNOR’S SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.**—Driver
2. **Number of posts.**—3 (Three)
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazette)
4. **Scale of Pay.**—i) Pay Scale for Regular Incumbents: Pay Band Rs.5910 - 20200 + Grade Pay Rs.2000/-
- ii) Emoluments for Contract employees : Rs 7910/- per month as per details given in Col. 15- A.
5. **Whether Selection post or non-selection post.**—N.A.
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 & 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relax- able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax-able at the discretion of the recruiting agency in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.—(A) **ESSENTIAL** (i) Should be Middle pass or its equivalent from a recognized Board of School Education/Institution.

(ii) Must possess valid driving license for the plying of heavy/light vehicles in Hilly Terrain.

(B) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Not Applicable.

9. Period of probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, Transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be; failing which on secondment basis/ transfer basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—On secondment /transfer from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Govt. Departments.

12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce and practical test for driving and maintenance skill of the candidate. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, A.E. Mechanical, HPPWD and Manager /Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing authority. Passing of practical test shall be mandatory.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under the policy the **Driver** in the Department of Governor's Secretariat, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSB.—The Secretary to Governor after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading News papers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Driver** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7910/-per month (which shall be equal to minimum of Pay band + grade pay). An amount equal to 3% of the contractual amount as annual increase for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary to Governor H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e Secretary to Governor.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Secretary to Governor from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-B** appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.7910/-per month(which is equal to the minimum of Pay Band + Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 3% of the minimum of Pay band+ Grade Pay of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An Official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The Woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/ Scheduled Tribes /other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons or posts.

“Annexure-B”

Form of contract/agreement to be executed between the Driver and the Government of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh

This agreement is made on this -----day of -----in the year between Shri/Smt.-----S/OD/O Shri -----R/O-----
-----contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND the Governor of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Driver** on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Driver** for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____. And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **7910/-** per month.

3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Driver** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Driver** He will not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Driver** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An Official appointed on contract bases who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of Women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. -----

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1 -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

सामान्य प्रशासन विभाग
ख-शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2010

संख्या जी.ए.बी.-ए(3)-13/2004.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सचिवालय में धोबी, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती आरै प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय धोबी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव।

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में धोबी, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—धोबी
2. **पदों की संख्या.**—1(एक)
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. **वेतनमान.**—वेतनमान में वेतन बैंड रू0 5910—20200 + रू0 1900 ग्रेड पे
5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—अचयन पद ।
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—लागू नहीं ।
7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.**—लागू नहीं ।
8. **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.**—आयु : लागू नहीं । शैक्षणिक योग्यता : लागू नहीं ।
9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेंडमैन्ट आधार पर ।

11 प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा.—धोबीमेट में से, जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेंडमैन्ट आधार पर ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरक पद में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि संभरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरक पद में अपने कुल सेवा काल/तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो/के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, यहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज़ आर्मड फोरसिज़ परसोनेल/रिजर्वेशन ऑफ वकैन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज़/रूलज़, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन/रिजर्वेशन ऑफ वकैन्सीज़ इन हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्नीकल सर्विसीज़/रूलज़, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरक पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी; यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरियता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी भी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा.— जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—लागू नहीं ।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बावत जारी किये अनुदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा इन नियमों, के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. GAB-A(3)-13/2004 Dated 24-5-2010 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, 24th May, 2010

No. GAB-A(3)-13/2004.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Dhobi, Class-III (Non-Gazetted) in Himachal Pradesh Governor's Secretariat as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Dhobi, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Secretary.

ANNEXURE-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DHOBI (CLASS-III NON-GAZETTED) IN THE GOVERNOR'S SECRETARIAT (HOUSEHOLD) HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the post.**—Dhobi
- 2. Number of posts.**—One (1)
- 3. Classification.**—Class-III (Non-Gazetted)

4. **Scale of Pay (be given in expanded notation).**—Pay Band in the Pay Scale of Rs. 5910-20200 + Grade Pay Rs. 1900/-
5. **Whether Selection post or non-selection post.**—Non-Selection.
6. **Age for direct recruitment.**—Not Applicable.
7. **Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.**—Not Applicable.
8. **Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.**—Age : Not Applicable. *Education Qualification* : Not Applicable.
9. **Period of probation if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, Transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.**—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which Promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Dhobi Mate with 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by secondment basis from the incumbents of this post working in the identical pay scale from the other H.P. Government Department.

(1) in all cases of promotion, the continuous service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for appointment/promotion subject to the condition that adhoc appointment /promotion in the feeder category have been made, after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

(i) Provided that in all the cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service(including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder posts in view of the provisions referred to above, all person senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above for junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall process the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and promotion Rules for the post, which ever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provision of Rule-3 of Demobilised armed Forces Personnel(reservation of vacancies in Himachal State Non Technical Service) Rules,1972 and having been given the benefit of seniority

there under the recruited under the provisions Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under;

(2) Similarly, in all the cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service if the adhoc appointment /promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P rules;

Provided that inter seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not Applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not Applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/Scheduled Tribes /other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons or posts.

सामान्य प्रशासन विभाग ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2010

संख्या जी.ए.डी-बी-(ए)3-3/2008.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्त क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सचिवालय में चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित), पद के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या जीएबी-1ए (3)-14/97 तारीख 27-9-1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1999 निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई भी नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव।

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय चपरासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—चपरासी
2. पदों की संख्या.—8(आठ)
3. वर्गीकरण.—वर्ग-IV (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—पे बैंड 4900-10680 रुपये + 1300/- रुपये ग्रेड वेतन
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ.—6200/- रुपये प्रतिमास की दर से कॉलम 15-क में दिए गए ब्यौरे अनुसार।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृंद को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—अनिवार्य.—(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास या इसके समतुल्य होना चाहिए ।

(ख) **वांछनीय अर्हता.**—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा के आधार पर, नियुक्त कर्मचारी कॉलम 15—क में दर्शाई गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथा कथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा उक्त विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि भर्ती प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15क. संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए पद पर चयन.—1. (क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(I) **संकल्पना.—**इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.—**सचिव, राज्यपाल, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्

रिक्त पदों के ब्योरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और इन नियमों में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन, नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार नियुक्त चपरासी को 6200/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम + ग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष(वर्षों), के लिए पद के वेतन बैंड के न्यूनतम + ग्रेड वेतन का 3% के बराबर रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VI I) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/— रुपए की नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी (जो वेतन बैंड के न्यूनतम + ग्रेड वेतन के बराबर होगी)। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में पद के वेतन बैंड के न्यूनतम + ग्रेड वेतन का 3% के बराबर वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सम्बद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए भी संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक ही स्थान पर पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध—“ख”

चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्रीनिवासीसंविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश राज्यपाल के मध्य सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ----- को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपरासी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में..... से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/— रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त चपरासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त चपरासी को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चपरासी कर्तव्य (ड्युटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, एक ही स्थान पर पांच वर्ष की सेवा अवधिपूर्ण करने के पश्चात् आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी, की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ जी0 पी0 एफ0/ई0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department's Notification No. GAD-B-(A)3-3/2008 Dated 24-5-2010 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th May, 2010

No. GAD-B-(A)3-3/2008.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Peon -Class-IV (Non-Gazetted) in Himachal Pradesh Governor's Secretariat as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:

1. Short title and Commencement.—1. These rules may be called the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Peon Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—1. The Himachal Pradesh Governor's Secretariat Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1999 notified vide this Department's Notification No. GABIA(3)- 14/ 97 Dated 27-9-1999 are hereby repealed.

2. Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF Peon (CLASSIV, NON-GAZETTED) IN THE GOVERNOR'S SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Peon

2. Number of posts.—8 (Eight)

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazette)

4. Scale of Pay.—(i) *Pay Scale for Regular Incumbents.*—Pay Band in the Scale of Rs. 4900-10680 + Rs.1300 as Grade Pay.

(ii) **Emoluments for Contract employees.**—Rs 6200/- per month as per details given in Col. 15-A.

5. Whether Selection post or non-selection post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years .

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relax- able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruiting agency in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.—(A) ESSENTIAL.—Should be Middle pass or its equivalent from a recognized Board/Institution.

(B) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Himachal Pradesh.

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Not Applicable.

9. Period of probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, Transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—N.A.

12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority.

15-A. Selection for appointment for the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) **CONCEPT.—**(a) Under the policy the **Peon** in the Department of Governor's Secretariat, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSB.—**The Secretary to Governor after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading News papers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) **CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—**The **Peon** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month (which shall be equal to minimum of Pay band + grade pay). An amount equal to 3% of the minimum of Pay band + grade pay of the post as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) **APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—**The Secretary to Governor H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) **SELECTION PROCESS.—**Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e Secretary to Governor.

(V) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—**As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Secretary to Governor from time to time.

(VI) **AGREEMENT.—**After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-B** appended to these Rules.

(VII) **TERMS & CONDITIONS.**—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month(which is equal to the minimum of Pay Band +Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 3% of the minimum of Pay band+ Grade Pay of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An Official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The Woman candidates will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/ Scheduled Tribes /other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax: Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons or posts.

Form of contract/agreement to be executed between the Peon and the Government of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh

This agreement is made on this -----day of -----in the year between
Shri/Smt.-----S/OD/O Shri -----R/O-----
-----contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND
the Governor of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Peon** on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Peon** for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____. And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **6200/-** per month.

3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Peon** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Peon**. He will not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Peon** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An Official appointed on contract bases who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of Women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

सामान्य प्रशासन विभाग
ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2010

संख्या जी.ए.डी.-बी.-(ए)3-4 / 2008.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्त क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सचिवालय में सन्देशवाहक, वर्ग-IV (अराजपत्रित), के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय सन्देशवाहक, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या जीएबी-1ए (3)-15/97 तारीख 27-9-1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय सन्देशवाहक, वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1999 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई भी नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव।

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय सन्देशवाहक वर्ग-IV (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.— सन्देशवाहक
2. पदों की संख्या.—2(दो)
3. वर्गीकरण.—वर्ग-IV (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—4900-10680 रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड + 1300/- रुपए का ग्रेड वेतन।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ.—स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे अनुसार 6200/- रुपए (वेतन बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड वेतन अर्थात् 4900 रुपये + 1300 रुपये) प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—लागू नहीं
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त

निकायों के ऐसे कर्मचारीवृंद को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्ति ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती अभिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—
(क) अनिवार्य अर्हता.—किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास या इसके समतुल्य ।

(ख) वांछनीय अर्हता.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—लागू नहीं ।

9. परीक्षा की अवधि यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथा कथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि भर्ती प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15क. संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए पद पर चयन.—1. (क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धों और शर्तों के अधधीन की जाएगी:—

(I) **संकल्पना.—**इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में सन्देशवाहक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.—सचिव, राज्यपाल, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरा, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताएं और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन, नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार नियुक्त सन्देशवाहक को 6200/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतन बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष(वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में संविदात्मक रकम के तीन प्रतिशत के बराबर नियत समेकित रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्त.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/— रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतन बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम का तीन प्रतिशत के बराबर वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सम्बद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए भी संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है जहां कहीं प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0' एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

संदेशवाहक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्रीनिवासीसंविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश राज्यपाल के मध्य सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ----- को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने **संदेशवाहक** के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार **संदेशवाहक** के रूप में..... से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/— रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक **संदेशवाहक** एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त **संदेशवाहक** को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त **संदेशवाहक** कर्तव्य (ड्युटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक ही स्थान पर पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी, की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ जी0 पी0 एफ0/ई0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department's Notification No. GAD-B-(A)3-4/2008 Dated 24-5-2010 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th May, 2010

No. GAD-B-(A)3-4/2008.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Messenger, Class-IV (Non-Gazetted) in Himachal Pradesh Governor's Secretariat as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:

1. Short title and Commencement.—1. These rules may be called the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Messenger Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—1. The Himachal Pradesh Governor's Secretariat Messenger, Class-IV (Non-Gazetted) ministerial services Recruitment and Promotion Rules, 1999 notified vide this Department's Notification No.GAB-IA(3)- 15/ 97 Dated 27-9-1999 are hereby repealed.

2. Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary.

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MESSENGER
(CLASS-IV, NON-GAZETTED) IN THE GOVERNOR'S SECRETARIAT
HIMACHAL PRADESH**

1. Name of the post.— Messenger

2. Number of posts.—2 (Two)

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazette)

4. Scale of Pay.—(i) *Pay Scale for Regular Incumbents.*—Pay Band in the Scale of Rs. 4900-10680 + Grade Pay Rs. 1300.

(ii) **Emoluments for Contract employees.**—Rs 6200/- Minimum of the Pay Band + Grade Pay i. e. Rs. 4900/- + Rs. 1330 per month as per details given in Col. 15-A.

5. Whether Selection post or non-selection post.—N.A.**6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years .**

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruiting agency in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.—(A) ESSENTIAL.—Should be Middle pass or its equivalent from a recognized Board/Institution.

(B) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Himachal Pradesh.

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Not Applicable.**9. Period of probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.****10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, Transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.**

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—N.A.

12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority.

15-A. Selection for appointment for the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) **CONCEPT.—**(a) Under the policy the **Messenger** in the Department of Governor's Secretariat, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSB.—**The Secretary to Governor after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading News papers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) **CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—**The **Messenger** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 6200/-per month (which shall be equal to minimum of Pay band + grade pay). An amount equal to 3% of the contractual amount as annual increase in the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) **APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—**The Secretary to Governor H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) **SELECTION PROCESS.—**Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e Secretary to Governor.

(V) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—**As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Secretary to Governor from time to time.

(VI) **AGREEMENT.—**After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-B** appended to these Rules.

(VII) **TERMS & CONDITIONS.**—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6200/-per month(which is equal to the minimum of Pay Band +Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 3% of the minimum of Pay band+ Grade Pay of the post for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An Official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The Woman candidates will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Form of contract/agreement to be executed between the Messenger and the Government of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh

This agreement is made on this -----day of -----in the year between Shri/Smt.-----S/O D/O Shri -----R/O-----
-----contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND the Governor of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Messenger** on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Messenger** for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____. And information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **6200/-** per month.
3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual **Messenger** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Messenger**. He will not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Messenger** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An Official appointed on contract bases who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of Women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

**सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग -ख**

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2010

सूख्या जी.ए.डीबी.-(ए)3-5/2008.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सचिवालय में चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती आरै प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन आरै व्यावृत्ति.—(1) इस विभाग की अधिसूचना सूख्या जीएबी.1ए (3)-16/97 तारीख 27-9-1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), लिपिकीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 1999 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई भी नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव ।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में चौकीदार वर्ग-IV (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—चौकीदार
2. पदों की संख्या.—1 (एक)
3. वर्गीकरण.—वर्ग-IV (अराजपत्रित)
4. वेतनमान—(i) स्थाई पदधारी के लिए वेतनमान.—वेतनमान 4900—10680 के पे बैंड, जमा 1300/— रु0 ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—6200/रुपये—स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रतिमास ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिये पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर ,निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्व ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती अभिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य.—सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान से प्राइमरी पास होना चाहिए ।

(ख) वांछनीय अर्हता.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—लागू नहीं ।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर, भर्ती द्वारा । संविदा के आधार पर, नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधारपर, किया जाएगा यदि, भर्ती प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धों और शर्तों के अध्वधीन की जाएगी.—

(I) सकल्पना.—(क) इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय, के कार्यालय में चौकीदार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.—सचिव, राज्यपाल, पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और इन नियमों में विहित अर्हताएं अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा वरिष्ठता/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ.—संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार को 6200/— रुपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतन बैंड के न्यूनतम + ग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्तवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में संविदात्मक रकम के 3 % के बराबर नियत समेकित रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् सचिव, राज्यपाल द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों में संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/— रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम का 3% —रुपये के बराबर वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सम्बद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठता/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक माह की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए भी संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो जहां कहीं प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित परिलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध—“ख”

चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चौकीदार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार चौकीदार के रूप में..... से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6200/— रुपये प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त चौकीदार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त चौकीदार को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चौकीदार कर्तव्य (ड्युटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए जाने के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department's Notification No. GAD-B-(A)3-5/2008 Dated 25-5-2010 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2010

No. GAD-B-(A)3-5/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Chowkidar -Class-IV (Non-Gazetted) in Himachal Pradesh Governor's Secretariat as per Annexure-A attached to this notification, namely:

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Chowkidar Class-IV (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Governor's Secretariat Chowkidar Class-IV (Non-Gazetted) ministerial services Recruitment and Promotion Rules 1999 Notified vide this Department's Notification No.GAB-IA(3)-16/97 Dated:27-9-1999 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been made valid under these Rules.

By order,
Sd/-
Secretary.

Annexure-“A”

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF Chowkidar CLASS-IV
(NON-GAZETTED) IN THE GOVERNOR'S SECRETARIAT HIMACHAL PRADESH**

- 1. Name of the post.**—Chowkidar
- 2. Number of posts.**—1(One)
- 3. Classification.**—Class-IV (Non-Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**—(i) **Pay Scale for Regular Incumbents**—Pay Band in the scale of Rs. 4900-10680 + Grade pay of Rs. 1300/-

(ii) **Emoluments for Contract employees.**—Rs 6200/- (minimum of the pay band + Grade pay i.e. Rs. 4900 +1300/-) as per details given in col. 15-A).

5. Whether Selection post or non-selection post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relax- able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation /Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruiting agency in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.—
(a) **ESSENTIAL.**—Should be primary pass from a duly recognized School/Institution.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATION.**—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Himachal Pradesh.

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Not Applicable.

9. Period of probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, Transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis as the case may be . The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—N.A.

12. If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority as the case may be considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority -as the case may be.

15-A. Selection for appointment for the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under the policy the **Chowkidar** in the Department of Governor's Secretariat, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSB The Secretary to Governor after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading News papers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Chowkidar** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.6200/-per month (which shall be equal to minimum of pay band +Grade pay).An amount equal to 3% of the contractual amount as annual increase for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary to Governor H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e Secretary to Governor.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. Secretary to Governor from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-B** appended to these Rules.

TERMS & CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6200/-per month (which shall be equal to the minimum of Pay Band+ Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 3% of the minimum of the Pay Band+Grade Pay of the post for further extended years and no other allied benefits such as seniority /selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An Official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The Woman candidates will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/ Scheduled Tribes /Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons or posts.

Form of contract/agreement to be executed between the Chowkidar and the Government of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh

This agreement is made on this -----day of -----in the year between Shri/Smt.-----S/OD/O Shri -----R/O-----contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND the Governor of Himachal Pradesh through Secretary to Governor, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Chowkidar** on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Chowkidar** for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____. And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.6200/- per month. 3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Chowkidar** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Chowkidar**. He will not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Chowkidar** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of Women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1 -----

(Name and full address)

2. -----

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

**SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO THE MAIN AGREEMENT
DATED 18-06-2010, UNDER SECTION 41
OF THE LAND ACQUISITION ACT, 1894**

THIS SUPPLEMENTARY AGREEMENT made on this 21st day of June, Two Thousand Ten between Lafarge India Pvt. Limited, a Company registered under the Company's Act, 1956 and having its registered office at Bakhtawar, 14th Floor, 229, Nariman Point Mumbai-400021, Maharashtra State, through Rakesh Ram S/o Shri Gyan Chand Ram appointed by the Company as its Attorney (hereinafter called "the Company" which expression shall include its heirs, successors and assigns) of the one part and the Government of Himachal Pradesh through Under Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter called the "Government", which expression shall include his successors in office and assigns) of the other part.

Whereas, in pursuant to the application of the Company for acquisition of land for its Mining purpose in village Talehan, Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh, the Government of Himachal Pradesh have entered into an agreement dated 18.06.2010 with the company under section 41 of the Land Acquisition Act, 1894 to acquire the Land on behalf of the Company under provisions of the Act, the pieces or parcels of land described and delineated in the Schedule annexed with the agreement, measuring 565-19-7 Bighas, the Mining purpose of the said company.

And whereas the said Government has issued a notification under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, showing the intention of the Government for acquisition of the said Land for the company. However, due to changes in the jamabandi, the said notification under section 4 of the Act is showing differences in three Khasra Nos. in the area mentioned in the above said agreement under section 41 of the act between company and the Government. Therefore, the said Government has called upon the Company to enter into this present SUPPLEMENTARY agreement with the "Government" to this effect, hereafter contained.

Now, these presents witness and it is hereby agreed and declared as follows:

1. That due to changes in Jamabandi, the variation in the area of Khasra Nos. as per Sec. 4 notification *vis-a-vis* in agreement u/s 41 are as follows:

Sl. No.	Khasra Number	Area in Section 4 (As per Jama Bandi 2001-2002)			Area in Agreement u/s 41 (As per Jamabandi 2005-06)			Difference (Excess in Section 41 Agreement)		
		Bigha	Bishwa	Bishwansi	Bigha	Bishwa	Bishwansi	Bigha	Bishwa	Bishwansi
1	80	0	5	2	0	5	12	0	0	10
2	604	0	3	6	0	3	16	0	0	10
3	701	0	12	2	1	12	2	1	0	0
	Total	1	0	10	2	1	10	1	1	0

2. That the pieces or parcels of land described and delineated in the notification under section 4 of the Act in respect of the above said Khasra Nos. will be considered as part and parcel of the agreement under section 41 of the Act between the parties in place of the description of the above said three khasra Nos. mentioned in Schedule thereto annexed with the agreement situated in villages Talehan, Tehsil Karsog, District Mandi of Himachal Pradesh.

3. That the rest contents of the above said agreement under section 41 of the act between the parties shall remain the same and legally binding with full force on all concerned parties/persons.

4. That all the contents of the present SUPPLEMENTARY agreement shall be read with and as part and parcel of the previous agreement under section 41 of the act between the parties for acquisition of land for Mining purpose of the company in village Talehan, Tehsil Karsog, District Mandi of Himachal Pradesh.

IN WITNESS whereof the seal of the Company has been affixed and the Government of the State of Himachal Pradesh hereinto set his hand and seal, the day, month and year hereinabove mentioned.

WITNESSES:

1. _____

2. _____

1. _____

2. _____

Sd/-

Rakesh Ram

Asstt. Vice President

For and on behalf of

Lafarge India Pvt Limited.

For and on behalf of

Government of Himachal Pradesh.

Sd/-

Through: Under Secretary (Industries) to the
Government of Himachal Pradesh

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मनीकरण जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश

...

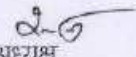
विशेष क्षेत्र मनीकरण के वर्तमान भूमि उपयोग को अपनाने हेतु

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि मनीकरण विशेष क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर तैयार करके दिनांक 12 नवम्बर, 2010 को असाधारण राजपत्र में जनता की आपत्तियों व सुझावों को आमन्त्रित करने हेतु हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 की अधिनियम संख्या 12) की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था। वर्तमान भूमि उपयोग के मानचित्रों एवं रजिस्ट्रों की प्रतियां निरीक्षण हेतु सदस्य सचिव, साडा मनीकरण एवं योजना अधिकारी, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, कुल्लू व प्रधान ग्राम पंचायत, मनीकरण एवं कसोल के कार्यालयों में रखी गई थी। इस सम्बन्ध में जनता से कुल 5 (पांच) आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। आपत्तियां मात्र व्यक्तिगत भवनों की प्रविष्टियों व उनसे जुड़े विवरणों के बारे में थीं। अतः उनकी सुनवाई अध्यक्ष, साडा मनीकरण एवं उपायुक्त, कुल्लू द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 24.05.2010 को करने के उपरान्त दस्तावेजों में बांछित संशोधन कर दिया गया है। उक्त वर्तमान भूमि उपयोग को उपरोक्त अधिनियम की धारा-15 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अपना लिया जाता है। वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र व रजिस्टर की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

1. सदस्य सचिव, साडा मनीकरण एवं योजना अधिकारी,
मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, कुल्लू।
2. प्रधान ग्राम पंचायत, मनीकरण एवं कसोल जिला कुल्लू।

यह भी सूचित किया जाता है कि विशेष क्षेत्र मनीकरण हेतु भूमि उपयोग पर उपरोक्त अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाता है और इस धारा के प्रभावी होने से कोई भी व्यक्ति/स्थानीय प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मनीकरण की लिखित अनुमति के बिना न तो वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये भू उपयोग से भिन्न उपयोग बदल सकता है और न ही कोई विकास भूमि उपयोग के विरुद्ध किसी उद्देश्य के लिए कर सकता है।

स्थान : कुल्लू
दिनांक : जून, 2010


 अध्यक्ष,
 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
 मनीकरण एवं उपायुक्त, कुल्लू।

**SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY, MANIKARAN
HIMACHAL PRADESH**


**DRAFT NOTICE FOR ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP FOR
MANIKARAN SPECIAL AREA**

Notice is hereby given that Existing Landuse Map of Manikaran Special Area was prepared and published in official gazette dated 12th Nov, 2009, for inviting public objections and suggestions under Sub-Section (1) of Section-15 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and copies of which were placed in the office of Member Secretary, SADA, Manikaran -cum- Planning Officer, Divisional Town Planning Office, Kullu and in the office of the Pradhan, Gram Panchayat, Manikaran and Kasol for inspection.

Only 5 nos. objections were received on the said document from individual owners. The objections were primarily with respect to missing entries of storeys of individual buildings or details thereof. The objections were heard and decided by the Chairman, SADA, Manikaran -cum- Deputy Commissioner, Kullu in personal hearing on dated **24.05.2010** in the chamber of his office. Necessary amendments in the document to give effect to the decisions of hearing were made accordingly. The existing landuse is, therefore, now adopted & frozen and copies of same alongwith Registers are placed for public inspection in the following offices:-

1. The Member Secretary, SADA, Manikaran -cum- Planning Officer, Divisional Town Planning Office, Kullu (HP).
2. Pradhan, Gram Panchayat, Manikaran and Kasol, District Kullu (HP).

It is hereby notified that the existing landuse map & register of Naggar Special Area as prepared & adopted under Sub-Section (3) of Section-15 and frozen with immediate effect under Section-16 of aforesaid Act and no person/local authority henceforth shall institute or change use of land or carry out any development of land for any purpose other than indicated in the existing landuse map of Manikaran Special Area without prior permission in writing from the SADA, Manikaran.


Chairman,
SADA, Manikaran-cum-
Deputy Commissioner,
Kullu (HP).

No.SADA (Manikaran)/10-

165-200

Dated 10-6-2010